

साउथ इण्डिया से मांग उठी, अब संसद की कुछ बैठक दक्षिण भारत में भी हों

वाय.एस.आर. कांग्रेस के तिरुपति से सांसद ने संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू को पत्र लिख कर यह मांग की

—लक्ष्मण बैंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। अब दक्षिण भारत से मांग उठ रही है कि दक्षिण भारत में संसद की मीटिंग कराई जाए जैसे कर्नाटक विधानसभा की बैठक बेलागावी में भी होती है। दक्षिण भारत से संसदीय बैठकों का विकेन्द्रीकरण करने की बात की जा रही है। इस तरह के विचार का समर्थन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भी किया था।

वाय.एस.आर.सी.पी. के तिरुपति के सांसद एम. गुरुमूर्ति ने संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू को इस बारे में पत्र लिखा है, जिसका समर्थन तमिलनाडु के सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी किया। तिरुपति सांसद ने इस मांग के पीछे तर्क और एतिहासिक परिप्रेक्ष्य पेश किया और कहा कि ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा और दिल्ली के खराब मौसम से सांसदों को

- तमिलनाडु से निर्वाचित सांसद कार्ति चिदम्बरम सहित कई दक्षिण भारत के सांसदों ने इस मांग का समर्थन किया।
- इन सांसदों के अनुसार, अम्बेडकर व वाजपेयी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। वाजपेयी का कहना था, यह प्रशासनिक कदम देश में एकता का भाव और मजबूत करेगा, तथा संसद को जनता के नज़दीक लायेगा।
- इस मांग के समर्थक सांसदों का यह भी कहना था, इस कदम से सभी सांसदों को दिल्ली की भीषण सर्दियों के मौसम से राहत मिलेगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
- एतिहासिक दृष्टि से यह सच है कि, 1988 में भी ऐसा एक प्रस्ताव प्राइवेट मੈम्बर बिल के मार्फत लोकसभा में उठाया गया था, पर अन्य प्राइवेट मੈम्बर बिल की भाँति, यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया था। पर, अब शायद इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेने का समय आ गया है, तथा इससे यह मैसजे जायेगा कि संसद वाकई में पूरे देश की राष्ट्रीय संस्था है।

आवागमन से राहत मिलेगी और काम बेहतर ढंग से हो सकेगा। एतिहासिक

उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि अम्बेडकर और वाजपेयी जी ने संसद के सत्रों के विकेन्द्रीकरण की बात की थी जिसमें एकता व सबको साथ लेकर चलने की भावना को बल मिलेगा तथा संसद सभी क्षेत्र के लोगों के करीब लाया जा सकेगा। अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्री एम. गुरुमूर्ति ने हर साल संसद की दो बैठकें दक्षिण भारत में करवाने का सुझाव दिया और उम्मीद जताई कि सरकार इस सार्थक सुझाव पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगी। इसी तरह का विचार 1968 में एक सदस्य ने निजी बिल के मार्फत पेश किया था पर विधेयक पारित नहीं हो सका, पर अब समय आ गया है कि ऐसा कदम उठाया जाए अगर संसद की बैठकों का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए तो जनता को लगेगा कि संसद उनके ज्यादा करीब आ गई है। इससे यह साबित करने में भी मदद मिलेगी कि संसद राष्ट्रीय निकाय है और सिर्फ नई दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है।

‘पूर्व सी.जे.आई. ने पूजा स्थल सम्बंधी विवादों को जन्म दिया’

नई दिल्ली, 02 दिसंबर कांग्रेस ने सोमवार को उपासना स्थल अधिनियम- 1991 को पूरी तरह से लागू करने की मांग उठाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अफसोस की बात है कि 20 मई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कुछ मौखिक “ऑब्जर्वेशन्स” दी थी, जिसने मंदिर-मस्जिद वाली याचिकाओं का रास्ता साफ किया है। भाजपा उसका भरपूर राजनीतिक फायदा उठा रही है।

- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा 20 मई 2022 को पूर्व सी.जे.आई. चंद्रचूड़ ने जो मौखिक टिप्पणी की थी उसके बाद से ही मस्जिदों व दरगाहों पर दावेदारी जताने की याचिकाओं की बाढ़ आ गई है।

हर जगह साम्प्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मगर 1991 में बने कानून को लागू करना अनिवार्य है। जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में सामने आए विभिन्न विवाद जैसे कि संभल में एक मस्जिद और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दावा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अडानी की मुश्किलें संसद तक ही सीमित नहीं

बांग्लादेश ने भी अडानी पावर कम्पनी से अपनी बिजली की खरीद आधी की

—श्रीनन्द झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। जहाँ गौतम अडानी विवाद के कारण संसद में गतिरोध बना हुआ है, वहीं, इस दिग्गज व्यवसायी को पड़ोसी बांग्लादेश में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने “अडानी पावर” से की जाने वाली बिजली की माँग आधी कम कर दी है। यह तनातनी पिछले महीने उस समय शुरू हुई, जब “अडानी पावर” ने भुगतान में विलम्ब होने के कारण, बांग्लादेश को होने वाली सप्लाई घटाकर आधी कर दी थी। बताया जाता है कि इसके बाद, बांग्लादेश ने अडानी से कह दिया कि वे अब केवल आधी सप्लाई ही करें। अडानी ग्रुप, 25 साल के अनुबन्ध के तहत, बांग्लादेश को पावर-सप्लाई कर रहा है। यह अनुबन्ध 2017 में हुआ था, जब बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं। पावर-सप्लाई “अडानी पावर” द्वारा झारखंड में स्थापित की गई दो इकाइयों से की जा रही थी। इनमें से प्रत्येक की क्षमता करीब 800 मेगावॉट थी। रिपोर्टों के अनुसार, यह प्लॉट नवम्बर में केवल 4.1 प्रतिशत क्षमता के साथ चला। पिछली सदियों तक,

- अडानी पावर कम्पनी, अपने झारखण्ड स्थित पावर प्लांट की दो इकाइयों से, जिनकी पावर जनरेशन की क्षमता 16 सौ मेगावाट थी, से बांग्लादेश को नियमित बिजली सप्लाई कर रही थी, अब नवम्बर यह प्लांट 41 प्रतिशत क्षमता पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि, बांग्लादेश ने अडानी से बिजली खरीद आधी कर दी है।
- झगड़ा शुरू हुआ गत माह से, जब अडानी की कम्पनी ने बांग्लादेश को दी जा रही सप्लाई को आधा कर दिया था, भुगतान देरी से मिलने का बहाना करके। जवाबी कार्यवाही में बांग्लादेश ने अडानी की कम्पनी को पत्र लिख कर कहा, “अब आप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई आगे के लिए आधी ही कर दें।”
- अपृष्ट खबरों के अनुसार बांग्लादेश चाहता है कि अडानी अपनी बिजली सप्लाई की दर में भारी कमी करे, क्योंकि, भारत की अन्य पावर सप्लाई कम्पनियों लगभग औसतन 9.57 टका प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई कर रही हैं, जबकि, अडानी पावर कम्पनी 14.87 टन प्रति यूनिट की दर से बांग्लादेश को बिजली बेच रही है।

बांग्लादेश करीब 1000 मेगावॉट बिजली प्रतिमाह खरीद रहा था। “अडानी पावर” के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फर्म बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करती आ रही है, हालाँकि बढ़ाता जा रहा उधार एक बड़ी चिन्ता का विषय है। इसके कारण प्लांट का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने संविधान पर चर्चा की विपक्ष की मांग मानी

संभावना है कि मंगलवार से संसद के दोनों सदन में सुचारू रूप से काम होगा

—जाल खंभाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। संसद के दोनों सदन का काम-काज मंगलवार से शुरू हो सकता है क्योंकि मोदी सरकार ने कांग्रेस की इस माँग को स्वीकार कर लिया है कि संविधान पर दो दिन की विशेष चर्चा हो। राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रकार की चर्चा कराने के लिये सदन के सभापति को पत्र लिखा था। इसी प्रकार का एक पत्र 26 नवम्बर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखा था। संविधान पर चर्चा लोकसभा में 13 तथा 14 दिसम्बर को तथा राज्य सभा में 16 एवं 17 दिसम्बर को होगी। सरकार, संसद के निरन्तर गतिरोध के समाधान की खातिर, संविधान पर बहस कराने की विपक्ष की माँग पर सहमत हो गई है। ज्ञातव्य है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत, अर्थात्

- लोकसभा में 13 और 14 दिसम्बर को तथा राज्यसभा में 16 व 17 दिसम्बर को संविधान पर चर्चा होगी।
- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बारे में स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजा था।
- शुक्र में सरकार ने संविधान पर चर्चा कराने से इन्कार कर दिया था, इस वजह से 25 नवम्बर से शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद संसद में एक दिन भी काम नहीं हुआ।

25 नवम्बर से ही संसद टूट पड़ी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कार्यालय में सदन के सभी नेताओं की मीटिंग हुई तथा यह तय हुआ कि मंगलवार से सदन की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से शुरू हो जायेगी तथा उस दिन सदन में पहला विधेयक पेश एवं पारित हो जायेगा।

इस घटनाक्रम पर बयान देते हुये, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा “ऐसी आशा है कि मोदी सरकार दोनों सदन में कल (मंगलवार) से काम होने देगी।” शीतकालीन सत्र के आरम्भ से ही, दोनों सदन में कोई काम-काज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विपक्ष आसनों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सन् 2000 के मालपुरा दंगों में आठ को आजीवन कारावास

जयपुर, 2 दिसंबर। सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 24 साल पहले टांक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान, हत्या करने वाले अभियुक्तों इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाल अहमद और मोहम्मद हबीब को

- अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से इस निर्ममता पूर्ण घटना को अंजाम दिया। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही, अदालत की पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से निर्ममतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज होगी महाराष्ट्र के भाजपा विधायक दल की बैठक

पहले यह बैठक सोमवार 2 दिसम्बर को होने वाली थी

—जाल खंभाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। महाराष्ट्र में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग, जो 2 दिसम्बर को होनी थी, 3 दिसम्बर तक के लिये टाल दी गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री विजय रूपानी को महाराष्ट्र भाजपा के विधायक दल के नेता के चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है। रूपानी ने कहा कि दोनों पर्यवेक्षक जाकर, प्रत्येक विधायक से मिलेंगे तथा सम्बन्धित जानकारी पार्टी हाईकमान को देंगे। इसके बाद, हाईकमान के निर्देशानुसार, पार्टी नेता की घोषणा कर दी जायेगी। इस बीच, शिव सेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि उनके नेता तथा निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे महायुति सरकार के गठन में बाधा नहीं दें तथा पार्टी की भी कोई माँग नहीं है। शिंदे के नज़दीकी साथी शिरसाट ने कहा, “सब कुछ इतनी स्पष्टता के साथ कह देने के बाद, मेरे खयाल से उन (शिंदे) पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। वरिष्ठ नेता जो कुछ भी कहेंगे, वह हमें स्वीकार होगा। महायुति में कोई मतभेद नहीं है... मेरे खयाल से, नेताओं एकनाथ शिंदे, देवेन्द्र फडणवीस तथा

- केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पर्यवेक्षक बनाया गया है, वे सभी विधायकों से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।
- शिवसेना और एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट ने साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे सरकार गठन में बाधा नहीं दें और उनकी पार्टी की कोई मांग नहीं है।
- असल में शिंदे व उनकी पार्टी को लेकर भारी अटकलें लगाई जा रही हैं पर शिंदे ने अपने गांव से लौटने के बाद स्पष्ट कर दिया कि महायुति पूरी तरह से एक जुट है।
- इधर शिंदे के पुत्र को लेकर भी कई अटकलें चल रही हैं, जिनका उन्होंने खंडन किया और कहा कि वे किसी भी पद की दौड़ में नहीं हैं।

अजित पवार की विभागों के सम्बन्ध में मीटिंग होगी तथा सारी उलझनें दूर हो जायेगी। “एक्स” पर की गई एक पोस्ट में, एकनाथ शिंदे के पुत्र ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि वे नई महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं।

अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, “मुझे सत्ता में पद पाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ कि मैं राज्य मंत्रिमण्डल के किसी पद की दौड़ में नहीं हूँ।”

अस्वस्थ होने के कारण, थोड़े से समय के लिये अपने गृहनगर में ठहरने के बाद, एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति के सभी मंत्र एक-दूसरे के साथ हैं तथा नये मुख्यमंत्री की घोषणा जल्दी ही हो जायेगी।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का पिछले ढाई साल का काम इतिहास में याद किया जायेगा। यही कारण है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया तथा विपक्ष को नकार दिया, यहाँ तक कि उसे विपक्ष का नेता चुनने का अवसर भी नहीं दिया। महायुति के तीनों दलों के बीच अच्छी समझ-बूझ है।” लेकिन उनकी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को एक बार पुनः यह माँग की कि शिंदे के नेतृत्व में राज्य में हुये विकास-कार्य के आधार पर, उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकारी कर्मचारी को एक पद पर रहने का अधिकार नहीं

जयपुर, 2 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होता है। सक्षम अधिकारी नियमों की बिना अवहेलना किए उसका दूसरी जगह तबादला कर सकता है। इसके अलावा, अदालत को प्रशासनिक

- हाईकोर्ट ने कहा, जब तक नियमों की अवहेलना नहीं हो अदालत को तबादला आदेशों में देखल नहीं देना चाहिए।

और जनहित में किए गए तबादला आदेश पर दखल नहीं देना चाहिए, जब तक कि उसमें नियमों की अवहेलना नहीं हुई हो। अदालत ने कहा कि यदि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहली बार बांग्लादेश के कूटनीतिक संस्थानों पर तोड़फोड़ हुई

शेख हसीना के पलायन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी हिंसा पर अब भारत में उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया होने लगी है

—अंजन राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। बांग्लादेश में हिंदुओं के संस्थापनों पर लगातार हो रहे हमलों के निशान भारत के पूर्वी भाग व पूर्वोत्तर भाग की राजनीति पर भी दिखने लगे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बांग्लादेश काउन्सिलर ऑफिस पर हमला होना तथा पश्चिम बंगाल के कुछ राजनैतिक घटनाक्रम बांग्लादेश की हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। यह एक संकेत है कि भारत और बांग्लादेश के सम्बंधों में भारी बदलाव आ गया है और अगरतला में बांग्लादेश के कार्यालयों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। अगरतला में एक बड़ी भीड़ ने बांग्लादेशी कान्सुलेट पर हमला कर दिया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस विरोध प्रदर्शन की निंदा की और जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने

- पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी काउन्सिलर ऑफिस पर गुस्ताई भीड़ ने हमला किया और भारी तोड़-फोड़ की।
- अगरतला की एक बस पर बांग्लादेश में हुए हमले की खबर ने लोगों में भारी नाराज़गी पैदा कर दी।
- जहाँ जनता की उत्तेजना बढ़ रही है, वहीं प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया बेहद अटपटी है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, स्पष्ट है ममता बनर्जी ने बयान अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया था।
- इसके विपरीत प. बंगाल की एक इस्लामिक पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
- बांग्लादेश में जब तक अवामी लीग का राज था तब तक कट्टरपंथियों पर अंकुश था पर अब कट्टरपंथी मनमानी कर रहे हैं और अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर रही है।

देश छोड़ा है, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है, इस पर भारत में भारी गुस्सा है तथा उसी की वजह से यह अगरतला वाली घटना हुई है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा हो रही है। अभी तक हिंसा बांग्लादेश में ही हो रही थी,

भारत में इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखी गई, खासकर पश्चिम बंगाल में। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अंतरिम

सरकार से कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है, पर प. बंगाल में सब कुछ सामान्य था। पर इस बार त्रिपुरा का रुख अलग था। अगरतला से चलने वाली एक बस पर बांग्लादेश में हमला हुआ और इस घटना की जानकारी मिलने के साथ ही त्रिपुरा में उत्तेजक प्रतिक्रिया हो रही है। इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत हल्की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमलों को अनावश्यक रूप से उछाला जा रहा है। ममता बनर्जी के इस रुख का लक्ष्य सिर्फ अपने वोट बैंक (पश्चिम बंगाल के मुस्लिम) को संतुष्ट रखना है। उस समय बड़ी अटपटी स्थिति हो गई, जब पश्चिम बंगाल के एक इस्लामिक राजनैतिक दल ने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजित पवार की विभागों के सम्बन्ध में मीटिंग होगी तथा सारी उलझनें दूर हो जायेगी।

अनूप बरतरिया का गिरफ्तारी वारन्ट जमानती में बदलने से इंकार

जयपुर, 2 दिसंबर। चेक अनादरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-8 महानगर प्रथम ने लौन के पेटे जमा कराए गए करीब 2.59 करोड़ रुपए राशि के चेक बाउंड होने के मामले में

- अदालत ने कहा कि अदालती आदेश की जानकारी होने के बाद भी चारों आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी वारन्ट जमानती में नहीं बदला जा सकता।

डब्ल्यू.टी.पी. के प्रबंध निदेशक अनूप बरतरिया, रुचि बरतरिया, विरेन्द्र बरतरिया और सरोजनी बरतरिया के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)